DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 17 दिसंबर, 2022

बलबन के मकबरे समेत चार स्मारकों की सुधरेगी दशा

G20 की तैयारियां

- आर्कियोलाजिकल पार्क में मार्च में हो सकता है जी-20 बैठक से संबंधित कार्यक्रम
- कुतुबमीनार के पास स्थित इस पार्क में स्मारकों की केमिकल क्लीनिंग के साथ ही कराया जाएगा संरक्षण कार्य

वी के शुक्ला ● नई दिल्ली

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) जी-20 को लेकर मार्च में संभावित बैठक वाले कुतुब आर्कियोलाजिकल पार्क में स्थित अपने चार स्मारकों की दशा सुधारेगा। यहां के चार स्मारकों में बलबन का मकबरा, जमाली-कमाली स्मारक, राजों की बावली व गंधक की बावली में रंग-रोगन व साफ-सफाई के साथ छोटा-मोटा संरक्षण कार्य होगा। इन स्मारकों की केमिकल क्लीनिंग कर स्मारकों पर जमी धूल हटाई जाएगी।

महरौली आर्कियोलाजिकल पार्क स्थित जमाली कमाली स्मारक ● जागरण

आर्कियोलाजिकल पार्क, महरौली स्थित विश्व विरासत स्थल कुतुबमीनार से सटा 200 एकड़ में फैला पुरातात्विक क्षेत्र है। पार्क की अधिकतर जमीन दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के पास है। इसमें 80 से अधिक स्मारक या स्मारकों के खंडहर और आसपास वन क्षेत्र है। यह दिल्ली का एकमात्र क्षेत्र है, जहां कई वंशों के स्मारक मिलते हैं, लेकिन अधिकतर के बारे में जानकारी नहीं है कि उसे किसने बनवाया या वह किससे संबंधित है। इसमें 1060 ईस्वी में तोमर राजपूतों द्वारा निर्मित सबसे पुराना और प्रसिद्ध किला लाल कोट का खंडहर भी शामिल है। इसके बाद के काल के स्थापत्य अवशेष खिलजी वंश, तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज से संबंधित हैं। इसमें चार स्मारक एएसआइ के पास हैं। जी-20 के तहत एक बैठक यहां हो सकती है, लिहाजा एएसआइ सक्रिय हो गया है।

राजों की बावली

महरौली स्थित राजों की बावली के बारे में कहा जाता है कि कुतुबमीनार की नींव रखने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने 1211-36 के दौरान अपनी बेटी रजिया के लिए इस शाही बावली को बनवाया था। इस बावली का एएसआइ ने लंबे समय बाद पिछले साल संरक्षण कार्य करवाया है। बावली में मुख्य गेट के दरवाजे की मरम्मत की गई है, सीढ़ियों को ठीक किया गया है। बावली के एक भाग में बची सीढ़ी की मरम्मत भी कराई गई है।

गयासुद्दीन बलबन का मकबरा

इस आर्कियोलाजिकल पार्क में जमाली-कमाली मस्जिद के बाद गयासुद्दीन बलबन की कब्र को ही प्रमुख स्मारक माना जाता है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु 1287 में हुई थी। इससे दो साल पहले बलबन का बेटा मोहम्मद मुल्तान में मंगोलों के खिलाफ युद्ध में मारा गया था, जो खां शहीद के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। उसे भी यहीं दफनाया गया था। बलबन के मकबरे के अहाते में 2009 में हुई खोदाई से शाही कब्र निकली थी, जिसके बारे में यह पता नहीं चल सका है कि यह कब्र किसकी है।

जमाली-कमाली मस्जिद: इस मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर ने वर्ष 1528 के आसपास करवाया था। हजरत जमाली यहीं रहते और इबादत करते थे। वर्ष 1536 में मौलाना जमाली की मृत्यु के बाद उन्हें इसी मस्जिद के आंगन में दफनाया गया। उनके समीप उनके साथी कमाली की भी कब्र है। दोनों की कब्र साथ होने से इसे जमाली-कमाली की दरगाह कहते हैं। इनकी कब्रें मस्जिद के आंगन में हैं, इस कारण जमाली-कमली की मस्जिद नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है।

19 दिसंबर, 2022 दैनिक जागरण

जलजमाव मुक्त होंगे एयरपोर्ट और द्वारका : वीके सक्सेना

दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना एयरपोर्ट ड्रेन का निरीक्षण करते। साथ में डीडीए के अधिकारी ● सौजन्य से राजनिवास

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : रविवार को एयरपोर्ट ड्रेन और द्वारका के विभिन्न जलाशयों का निरीक्षण करने पहुंचे दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि अगले मानसून तक एयरपोर्ट ड्रेन और द्वारका के विभिन्न जलाशयों का निर्माण पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना पर अब तेजी से काम चल रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं देने से निर्माण में देरी हो चुकी है। उप-राज्यपाल रविवार को तीसरी बार दौरा कर कहा 20 मई तक निर्माण पूरा कर दिया जाए। दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से इस परियोजना को मई 2023 में पूरा किए जाने से द्वारका क्षेत्र में जलजमाव की समस्या नहीं रह जाएगी। मानसून के दौरान आइजीआइ एयरपोर्ट के दो ड्रेन से बड़ी मात्रा में पानी निकलता है, जिसकी वजह से जलजमाव होता है। इससे यात्रियों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार हवाई जहाज की उड़ानें भी निरस्त करनी पड़ती हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार द्वारका में प्रस्तावित जिन आठ जलाशयों का निर्माण प्रस्तावित है, उसमें तीन द्वारका के सेक्टर आठ में निर्मित होगा। दो जलाशयों का निर्माण सेक्टर 20 में होगा। सेक्टर आठ के जलाशय की क्षमता 13,700 क्यूबिक मीटर होगी। अन्य दो जलाशय सेक्टर 20 और 23 में विकसित किए जाएंगे, जिसकी संयुक्त क्षमता 25,700 क्यूबिक मीटर होगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, DECEMBER 17, 2022

Night Economy & Slum Rehab In Focus For Next Master Plan

At Review Meet, LG Stresses On User-Friendly Provisions

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The next Master Plan of Delhi (MPD) will focus on promoting night-time economy and slum rehabilitation. During a review meeting with Delhi Development Authority (DDA) officials on Friday, lieutenant governor VK Saxena examined a few initial chapters of the draft plan and emphasised on adding "user friendly" and "implementable provisions" regarding slum rehabilitation and giving special focus on developing Delhi as an economic hub with a vibrant nightlife.

"We are making changes step by step as desired by the LG and the exercise is expected to continue as of now. But we aim to complete the task soon," said a DDA official.

While the draft MPD 2041 was prepared after accommodating the suggestions and objections of public earlier this year, sources said Saxena had been reading the document "line by line" and getting specific provisions to encourage night economy and in situ development of slum clusters added to it. In August, a presentation was made before the LG during which he directed officials to ensure non-proliferation of slums and all necessary amenities to unauthorised colonies.

DDA OFFICIAL SAYS

We are making changes step by step as desired by the LG (pic) and the exercise is expected to continue as of now

While MPD 2041 initially talked about the night economy in general terms, the Authority, on the insistence of the LG, has now identified specific circuits. DDA has also identified cultural precincts and heritage zones to boost tourism. "Connaught Place, Chandni Chowk to Daryaganj, Khan Market and Hauz Khas will be developed as food and shopping circuits while Coronation Pillar to Kashmere Gate, Safdarjung Tomb to Qutub Minar, Humayun's Tomb to Safdarjung Tomb, and Shahjahanabad will be developed as heritage circuits," said an official. Specific provisions for redevelopment of Shahjahanabad and special areas with fixed timelines will also be its part.

Divided into two volumes and nine sections, the plan contains 22 chapters. Each of them will be discussed threadbare and specific provisions will be added in the next two-three meetings. The document is also being reviewed to ensure that the plan is easily comprehensible to people, an official said.

"Prevention of road encroachment, illegal parking and unauthorised construction and development of public spaces, repurposing of vacant land due to shifting of industries were other points highlighted in Friday's meeting," said an official.

MPD 2041, which was to be implemented early this year, got delayed for various reasons including no finalisation of the Green Development Area policy, proposed amendments made in Delhi Development Act by the Centre, and delay in incorporation of public suggestions.

In September, after the Supreme Court observed that the master plan can't remain in limbo, DDA officials clarified that it would be placed before the Authority in December, sent to the Union housing affairs ministry in January, and the final document would be published on or before April 30, 2023.

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 19 दिसंबर 2022

मई 2023 तक आईजीआई एयरपोर्ट और द्वारका को मिलेगी जलभराव से मुक्ति

■ **विस, नई दिल्ली :** जी-20 के दौरान आने वाले मेहमानों को एयरपोर्ट पर जलभराव की समस्या न हो, इसके लिए आईजीआई एयरपोर्ट और द्वारका सब-सिटी को अगले मॉनसून तक जलभराव से निजात मिल जाएगी। तब तक आईजीआई एयरपोर्ट का पानी नजफगढ़ ड्रेन में आने लगेगा। एलजी वी के सक्सेना की निगरानी में डीडीए इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम हो रहा है। मई 2023 तक इस प्रोजेक्ट पर काम पूरा हो जाएगा। इसी समय सीमा में द्वारका क्षेत्र में पांच झीलें भी बनाई जाएंगी। इन झीलों में मॉनसून के दौरान सड़कों पर बहने वाले पानी को एकत्रित किया जाएगा। इन पांच झीलों में 1.22 लाख क्यूबिक मीटर पानी एकत्रित होगा।

यह अहम प्रोजेक्ट पिछले दो साल से दिल्ली सरकार के पाय पेड़ों को काटने की मंजूरी न मिलने की वजह से रुका हुआ था। एलजी के दखल के बाद 20 नवंबर को इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। एलजी ने रविवार को इन

प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को ड्रेनेज काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। झीलों की साइट का भी एलजी ने दौरा किया। झीलों की खुदाई आदि का काम अगले महीने तक पूरा हो जाएगा।

2.5 किलोमीटर लंबे एयरपोर्ट के लिए करीब 72000 क्यूबिक मीटर मिट्टी हटाने की जरूरत है। इसमें से 8200 क्यूबिक मीटर मिट्टी हटाई जा चुकी है। इसके साथ ही लाइनिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। एलजी ने इसके लिए निर्माण कार्य अगले साल 20 मई तक पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

जोरों पर तैयारी

- एलजी ने निर्माणाधीन एयरपोर्ट ड्रेन और झीलों का निरीक्षण किया
- जी-20 के दौरान आने वाले मेहमानों को नहीं होगी परेशानी

इस समय आईजीआई में दो ड्रेन है, लेकिन यह बारिश के पानी को पूरी तरह नहीं निकाल पाती। इसकी वजह से तेज बारिश के समय एयरपोर्ट पर जलभराव होता है। इसकी वजह से द्वारका सेक्टर-8 में भी जलभराव होता है। जिसके बाद ही यहां लोगों को राहत देते हुए झील बनाने का निर्णय भी लिया गया है। इस प्रोजेक्ट को इसलिए भी तेज किया जा रहा है, ताकि अगले साल जी-20 के दौरान आने वाले डेलिगेट को कोई परेशानी न हो।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

Hindustan Times
NEW DELHI
SATURDAY
DECEMBER 17, 2022

CITY MASTER PLAN SHOULD BOOST NIGHT ECONOMY: LG

NEW DELHI: Lieutenant governor VK Saxena on Friday directed the Delhi Development Authority (DDA) to include specific provisions in the Master Plan of Delhi (MPD)-2041 to encourage night-time economy and lay out circuits to boost heritage tourism.

The DDA will send the draft MPD-2041 to the Union ministry of housing and urban affairs by the end of the year, said a senior official. DDA informed the Supreme Court in September this year that the Master Plan is likely to be notified by April 2023.

A senior official said, "The LG has asked DDA to have a special focus on and include specific provisions to encourage the Capital's night-time economy by identifying and developing heritage circuits."

Some of the night circuits proposed are Connaught Place, Khan Market and Hauz Khas, among others, said officials aware of the matter. HTC

CITY
SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
DECEMBER 18, 2022

Polls gone, G20 coming, shopping festival likely to be truncated affair

Atul.Mathur@timesgroup.com

New Delhi: The AAP government's ambitious Delhi Shopping Festival, which was slated to start in the last week of January 2023, is likely to be delayed.

While a little over a month is left, sources said the project was still in the planning stage and had yet to get financial approvals and a nod from the cabinet. With the government's focus now shifting towards the preparations for the G20 Summit and related events, sources said the festival might either get postponed or be held on a smaller scale with fewer markets participating in it.

They added that deputy chief minister Manish Sisodia was likely to review the progress of the project next week and might take a final call on the possible dates. A senior government official confirmed that no formal proposal was moved by the tourism department, the nodal department for the preparations and organising the festival.

OFFICIALS SAY

Deputy CM Manish Sisodia is likely to review the progress of the project next week and may take a call on the possible dates

Announced in the Rozgar Budget, the annual festival promised to create 1.5 lakh new jobs in five years. In July, chief minister Arvind Kejriwal announced that the festival would be held from January 26 to February 28, 2023 and all markets, shops and malls of Delhi would be facelifted and over 200 entertainment programmes with world-class opening and closing ceremonies would be held. The government had given the responsibility of the festival to the tourism department and Delhi Tourism and Transportation Development Corporation.

A senior government official said several consultations were held between the tourism department, DTTDC and Dialogue and Development Commission of Delhi in the second quarter of the financial year and a broad framework was prepared, but the project lost pace due to the civic and Gujarat assembly polls.

"A draft cabinet note with the observations of the finance department was prepared but the enforcement of the model code of conduct and election campaigning did not allow the cabinet meeting to be held," said an official.

Since the festival is to be held in several prominent marketplaces, officials said all stakeholders, including MCD, NDMC, DDA, local and traffic police, and several Delhi government departments, need to work in close coordination to make it successful.

"Most Delhi markets come under the civic body and its participation would be required at every stage. Since the new councillors have yet to take oath and the elections for mayor and deputy mayor are still three weeks away, the government may have to wait for necessary deliberations and approvals to execute a few projects," said an official.

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 17 दिसंबर

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 18 दिसंबर, 2022

मास्टर प्लान में रात्रि कालीन आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली मास्टर प्लान 2041 (एमपीडी-2041) में रात्रि कालीन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए कहा है। उन्होंने एमपीडी-2041 ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अधिकारियों के साथ बैठक की। ड्राफ्ट के कुछ अध्यायों की जांच कर उसमें जरूरी बदलाव के सुझाव दिए। नया मास्टर प्लान नियोजित विकास, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला और दिल्लीवासियों की सुविधा के अनुकूल होना चाहिए।

इस ड्राफ्ट को तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में डीडीए की बोर्ड बैठक में मंजूरी दी गई थी। इसका ड्राफ्ट नौ जून 2021 को जारी कर लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। 75 दिनों के अंतराल पर डीडीए को 33 हजार से अधिक आपत्तियां और सुझाव मिले। सभी आपत्तियों और सुझावों को डीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में जनसुनवाई के माध्यम से सुना गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना का मानना है कि बीते कुछ दशकों में दिल्ली में गंदगी बढ़ने के साथ झुग्गी और अनधिकृत कालोनियों की संख्या बढ़ी है।

डीडीसीए लीग

हितेन का ऑलराउंड खेल

दिल्ली रणजी प्लेयर हितेन दलाल (56 रन और 4/08) के ऑलराउंड खेल और स्वर्णिम बंसल (28), सिद्धार्थ जैन (2/10) की मदद से कश्मीरी गेट कोल्ट्स (116/5) ने डीडीए (110/10) को 5 विकेट से हरा दिया।

प्रदीप, अशोक चमके

प्रदीप मलिक (68 रन और 1/18), अशोक सोलंकी (18 रन और 4/25) और आयुष कुमार (2/29) के प्रयास से पीएमजी (159/6) ने सोनेट क्लब (158/10) को 4 विकेट से हरा दिया।

दिल्ली कोल्ट्स जीते

पार्थ गोस्वामी (71), सुमीत कुमार (3/44) और चेतन गोयल (2/18) की बदौत दिल्ली कोल्ट्स (232/6) ने रवि ब्रदर्स (167/10) को 65 रन से शिकस्त दी।

हर्षित का दमदार खेल

हर्षित सेठी (56 रन और 4/37) के दमदार खेल और अंकुर कौशिक (85) व पार्थ जैन (54) के अहम योगदान से दिल्ली कोल्ट्स (231/2) ने चांद खन्ना क्लब (227/10) को 8 विकेट से हरा दिया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
MONDAY, DECEMBER 19, 2022

Two Yamuna riverfront projects in contention for G20 summit events

Vibha.Sharma
@timesgroup.com

New Delhi: Two Yamuna riverfront project sites — Asita East and Baansera — are being considered for holding outdoor events or meetings for the upcoming G20 summit. Lieutenant governor VK Saxena is likely to inspect the two locations in the coming week.

A senior Delhi government official confirmed that the sites were under consideration for holding events at the summit, but a final decision was yet to be taken.

"A direction has been given to prepare the sites and a visit is likely soon. Depending upon the status and other factors, a decision on holding G20 meetings there will be taken," an official said.

Among the first projects undertaken by the Development Authority (DDA) as part of the Yamuna riverfront redevelopment, Asita East is spread over 197 hectares. Baansera is, on the other hand, spread over 12 hectares. Both are known for their natural habitats, floodplain forest, grassland, riverine grass, etc.

At Asita East, 90 hectares of the land is with DDA, while the remaining falls under the jurisdiction of Uttar Pradesh's irrigation department

TOI@G20

At Asita East, 90 hectares of the land is with DDA, while the remaining falls under the jurisdiction of Uttar Pradesh's irrigation department. The site, located on the eastern bank of the river (between Old Railway Bridge and ITO Barrage), was inaugurated in September this year.

"The project aims at restoring the ecological character of the floodplain and providing breathable public green space. We have planted 33.5 lakh riverine grasses and 4,000 trees here and developed a waterbody where 50,000-60,000 cubic metres of water is collected during monsoon," the official added.

Hundreds of bird species (including migratory birds) were spotted at Asita East this time, officials said. "Over 30 varieties of birds were spotted along the waterbody itself," the official said.

Baansera is the capital's first bamboo-themed park on the Yamuna riverfront. Its foundation was laid in August by the LG. DDA will plant 20,000 bamboo saplings of 15 varieties in the next monsoon season.

As of now, work is in progress at six places, including an extended portion of Asita West, Asita East (at 107 hectares of UP irrigation land) and Kalindi Biodiversity Park.

Build new drainage system for IGI by May '23, says LG

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: To address the long-pending problem of flooding of runways, terminals and surrounding areas of Terminal 3 of Indira Gandhi International Airport, the lieutenant governor has given a May 2023 deadline to officials to construct a new drainage system near Sector 8 in Dwarka for proper discharge of rainwater.

The two existing drains at IGI airport are insufficient for discharge of the huge amount of rainwater from the area, which has often resulted in severe waterlogging in and around the airport during heavy rains, causing disruption and cancellation of flights for several days, said the LG house.

"The project is fast progressing and will be completed by May 2023. DDA, at the same time, is also creating five water bodies in Dwarka region that will be used for storing the overflowing rainwater during the monsoons. Once completed, these water bodies will have the total storage capacity of 1.22 lakh CuM of water that will prevent the rainwater from flooding onto the streets," it added.

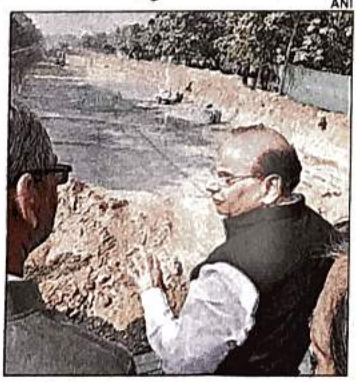

ANI

LG Vinai Kumar Saxena inspects the construction work of the new drainage system on Sunday

This project was stuck for the last two years due to pending permissions for tree cutting and translocation. It was after the LG's intervention that permission for tree translocation was given and the work on the airport drain commenced on November 20, said an official.

Vinai Kumar Saxena on Sunday inspected the construction site at Dwarka Sector and directed officials to enhance the manpower and other resources to complete the drainage work at the earliest, said a senior LG house official.

The digging and dredging work of water bodies is likely to be completed by next month.

The LG has issued strict instructions to finish the construction work by May 20 next year and warned against any laxity on part of the officials, he added.

The construction of drain within the airport premises will be done by the airport operator DIAL. Northern Railways is constructing a culvert over the railway land, and the remaining construction work will be carried out by DDA. The airport drain will be 20-metre wide and will have a depth of 2 metre.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS Hindustan Times --DATED NEW DELHI MONDAY DECEMBER 19, 2022

Green space along Yamuna likely venue for G20 events

Risha Chitlangia
risha.chitlangia@htlive.com

NEW DELHI: As the Capital gears up to host the G20 Leaders' Summit next year, one of the two newly-developed green spaces along the Yamuna being developed by the Delhi Development Authority (DDA) are being considered as the possible venue for the global event. The two sites are Asita East, located on the eastern bank of the Yamuna near the ITO barrage, and Baansera, a bamboo garden being developed near Sarai Kale Khan.

Senior officials of the land-owning agency said landscape and other infrastructure work is being undertaken on a war footing at the two sites, and DDA vice chairman Manish Kumar Gupta visited the sites on Sunday.

"The two sites are being considered for one or more meetings that are likely to be held in the national capital next year. Landscape work is being carried out, and other infrastructure such as walkways, toilets, bamboo structures for people to sit, etc are being developed at the two sites. A meeting centre made of bamboo is likely to be developed once the site is finalised," a DDA official said on condition of anonymity.

Delhi will host eight G20 events beginning March 1, 2023 with the meeting of G20 foreign ministers and culminating with the meeting of heads of governments and states on September 9-10, 2023.

Another official said that lieutenant governor Vinai Kumar Saxena visited the sites on December 10, and is likely to inspect them again this week.

"The two sites are being considered but no decision has been taken as yet. Works are going on at both the sites," the official said.

Asita East, which spreads over 90 hectares, has been developed by DDA as part of its ambitious Yamuna riverfront redevelopment project. Work on the project started in 2017 and it was inaugurated by the LG in September this year.

DDA officials say that the area was revived after largescale encroachment and illegal farming was removed in 2017-18. "We carried out landscaping work, cleaned the area, revived the waterbody and developed the infrastructure such as walkways, close to 30 acres of lawns with different varieties of grass," said an official.

The DDA has planted around to 4,000 trees and 3.35 million riverine grasses at this site, as of September. Around 100-150m of the area along major roads has been developed as a greenway, which is proposed to be a public recreation zone comprising walkways, spaces for congregation along with public amenities. Nearly 300m of the area along the Yamuna has been developed as an ecological zone with semi-permanent trails for people to walk up to the river.

The DDA has revived the waterbody, spread over five areas, and after the restoration work, DDA officials say, the area gets a lot of migratory birds.

"We are in the process of installing benches along the waterbody so that people can come and sit here. We have already developed public amenity blocks," said a senior official aware of the development.

The site is already being used to host events, such as the International Yoga day.

The LG had laid the foundation for Baansera, the second site in August for what is to become Delhi's first bamboo-themed park. Spread over 12 hectare, on completion the park will have over 25,000 bamboos.

A senior DDA official said developing Baansera has been a challenge as construction and demolition waste used to be dumped at the site.

"In a short span of time, we have been able to do a lot of work. The area was levelled before the plantation could be done and landscaping work is going on. Though work is being carried out at a fast pace, it will take some time for the area to be fully developed as a bamboo park," the official said, asking not to be named.

"The park will have amenities such as kiosks, huts for people to sit, watchtowers, wooden decks for cultural events or meetings, exhibition spaces and a greenway area along kachcha pathways. We are developing a large area with seasonal flower plantations," the official said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी DELHI ▶ 19 दिसम्बर, 2022 ▶ सोमवार

DATED

एलजी ने एयरपोर्ट ड्रेन व पांच वॉटर बॉडीज का किया निरीक्षण

▸▸ निरीक्षण के दौरान अफसरों से बात करते एलजी वीके सक्सेना।

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): आईजीआई एयरपोर्ट से आने वाले यात्रियों और द्वारका सबसिटी के लोगों को अगले साल मानसून के दौरान बाढ़ और जलभराव से बड़ी राहत मिलने वाली है। पिछले एक माह में एलजी एयरपोर्ट ड्रेन के तीन दौरे कर चुके हैं, उन्होंने रविवार को द्वारका सेक्टर-8 में निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल निकासी का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जनशक्ति और अन्य संसाधनों को बढ़ाने का निर्देश दिया।

दरअसल उपराज्यपाल वीके सक्सेना के मार्गदर्शन में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का आईजीआई एयरपोर्ट से बारिश के पानी को नजफगढ़ ड्रेन तक पहुंचाने के लिए चला प्रोजेक्ट मई 2023 तक पूरी हो जाएगा। साथ ही डीडीए द्वारका क्षेत्र में पांच वाटर बॉडीज भी बना रहा है जिनका उपयोग मानसून के दौरान वाटर फ्लो के स्टोरेज के लिए किया जाएगा। इन वाटर बाडीज में की स्टोरेज 1.22 लाख घन मीटर होगी जो बारिश के पानी को सड़कों पर बहने से रोकेगी। एलजी ने इन वाटर बॉडीज के लिए स्थलों का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को अगले महीने तक खुदाई और ड्रेजिंग का काम पूरा करने को कहा। 2.5 किमी लंबे एयरपोर्ट ड्रेन के लिए 72,000 घन मीटर मिट्टी हटाने की जरूरत होगी, जिसमें से अब तक 8200 घन मीटर मिट्टी निकाली जा चुकी है। लाइनिंग का काम भी एक साथ शुरू हो गया है ताकि काम की गति को बनाए रखा जा सके और यातायात में न्यूनतम बाधा उत्पन्न हो। एलजी ने अगले साल 20 मई तक निर्माण कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं और अधिकारियों की ओर से इसमें किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने की चेतावनी दी है। यह प्रमुख परियोजना पिछले दो वर्षों से दिल्ली सरकार से पेड़ काटने/स्थानांतरण की लंबित अनुमति के कारण अटकी हुई थी।

नई दिल्ली | रविवार, 18 दिसंबर 2022
अमर उजाला

तिमारपुर और भारत नगर के बीच साफ हुई नजफगढ़ ड्रेन

अमर उजाला ब्यूरो

- एलजी ने अधिकारियों संग क्षेत्र का निरीक्षण किया लोगों से की अपील नजफगढ़ नाले में न फेंके कचरा

नई दिल्ली। नजफगढ़ नाले का कायाकल्प और साहिबी नदी के पुनरुद्धार का काम तेजी से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत माल रोड ब्रिज और भारत नगर के बीच 7.5 किलोमीटर के हिस्से को समय से पहले पूरा किया गया। शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिकारियों के साथ मॉल रोड ब्रिज और भरत नगर के बीच के क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नाले के किनारे बसी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से कूड़ा सीधे नाले में न फेंकने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह हमारी विरासत है और इसे साफ रखना हम सब की जिम्मेदारी है।

बता दें कि लागत प्रभावी आंशिक गुरुत्वाकर्षण डी-सिल्टिंग प्रौद्योगिकी की मदद से इस 57 किलोमीटर लंबे नाले की सफाई और कायाकल्प पर काम किया जा रहा है। इसके पहले चरण में तिमारपुर और भरत के बीच काम सितंबर में शुरू हुआ। एलजी की निगरानी में शुरू हुए काम के ठोस परिणाम दिखाने लगे हैं। यहां वजीराबाद से तिमारपुर तक डी-सिल्टिंग का काम नवंबर में पूरा हो गया था। माल रोड ब्रिज और भारत नगर के बीच के हिस्से को जनवरी तक पूरा करना था, लेकिन इसे समय से पहले पूरा कर लिया गया है।

गाद से पानी का प्रवाह प्रभावित

- यह नाला सीवरेज और कीचड़ का स्थिर जलाशय बन गया है, जिसमें 80 लाख टन से अधिक ठोस कचरा गाद है। इससे पानी के प्रवाह गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। पिछले कुछ महीनों से किए जा रहे प्रयासों से 50 हजार टन से अधिक गाद निकाली गई है। इसके अलावा 27 हजार टन सतही कचरा-गाद को हटाया गया है।
- **कायाकल्प का काम तेजी से चल रहा :** एलजी की निगरानी में हो रहे नजफगढ़ ड्रेन का कायाकल्प तेजी से किया जा रहा है। पिछले पांच महीनों में कई सिविक एजेंसियों को इसमें शामिल किया गया। इसमें सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली मेट्रो सहित अन्य मिलकर सफाई को तेजी से कर रहे हैं। 57 किलोमीटर लंबे इस नाले में 122 नाले गिरते हैं। जो सीवेज का निर्वहन करते हैं। यह नजफगढ़ नाले को यमुना नदी का सबसे बड़ा प्रदूषक बनाता है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। सोमवार • 19 दिसम्बर • 2022 | राष्ट्रीय सहारा ---DATED----------

रेहड़ी वालों के अतिक्रमण से हो रही दिक्कत

कापसहेड़ा के मटके वाली गली में रोजाना प्रवेश वाली जगह से ही दोनों ओर रेहड़ी-पटरी वालों ने अतिक्रमण किया हुआ है। निवासियों की गाड़ी निकलने की जगह नहीं होती है। समझ में नहीं आता कि पुलिस और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को यह सब नजर नहीं आता। पूरा दिन गली में असामाजिक तत्वों का जमघट लगने के साथ लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाते हैं। इस तरह की अवांछित गतिविधियों से इस गली के लोग बहुत डरे हुए हैं। उनके साथ कभी भी कोई घटना घट सकती है। इस गली में रहने वाले शाम होते ही गली में बाहर जाने से डरने लगे हैं। हम गली वासियों का इस क्षेत्र के पुलिस आयुक्त से आग्रह है कि मटके वाली गली में चल रहे इस रेहड़ी-पटरी के गोरखधंधे को जल्द बंद करा यहां के निवासियों को सुरक्षा प्रदान करें।

दुखी निवासी, कापसहेड़ा

पेड़ों की कटाई व शौचालय का रखरखाव नहीं

शालीमार बाग के एबी और एए ब्लॉक के बीच बने पार्क और शौचालय का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है। यह पार्क डीडीए का है। यहां पार्क में छह महीने पहले शौचालय बना था, जिसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। इससे पहले इसका दरवाजा उखड़ गया है। नल टूट गए हैं। सीलन भी आ रही और साफ-सफाई नहीं होती है। पार्क के बर्फ डिपो के पास पेड़ बड़े होकर सड़क पर लटक गए हैं। इससे यहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है। यहां की दीवार भी इस कारण टूट सकती है। संबंधित विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान दें।

प्रवीन यादव, प्रेसिडेंट, एए ब्लॉक आरडब्ल्यूए, शालीमार बाग

सीजीएचएस डिस्पेंसरियों में पावर बैकअप नहीं

सीजीएचएस की डिस्पेंसरियों में पावर बैकअप की सुविधा नहीं है। अगर बिजली चली जाए तो डॉक्टर और स्टाफ खाली बैठ जाता है। सबको बताया जाता है कि बिजली नहीं है। मेरा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री और सीजीएचएस के अधिकारीयों

लोकमंच

से अनुरोध है कि सभी डिस्पेंसरियों में निरीक्षण करें और देखें कि पावर बैकअप सिस्टम दिया गया है कि नहीं। दिया गया है तो कहां गया।

नरेश कुमार, सेक्टर 5, आरकेपुरम

मोचीबाग स्थित श्मशान स्थल पर पानी की किल्लत

प्रशासनिक लापरवाही और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की घोर उपेक्षा के चलते सत्य निकेतन बस स्टैंड के पीछे स्थित गांव मोची बाग (अड़कपुर बाग मोची) की श्मशान भूमि पिछले कई माह से पानी के लिए तरस रही है। श्मशान भूमि में पानी न होने से अंतिम संस्कार की रस्म अदा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि यहां पानी के नाम पर एक बड़ी टंकी तो लगी है, लेकिन उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं होती। आश्चर्य की बात है कि अंतिम संस्कार के लिए लोगों को बाहर से पानी लाना पड़ता है। उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के चेयरमैन से अनुरोध है कि इस श्मशान भूमि की सुध लेते हुए तत्काल पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं।

सोमदत्त तंवर, गांव मोची बाग, नानक पुरा

सड़कें व फुटपाट अतिक्रमण से हों मुक्त

राजधानी के ज्यादातर मेट्रो स्टेशनों के नीचे और आसपास सड़कों व फुटपाथों पर रेहड़ी, खोमचों और बेटरी रिक्शा वालों द्वारा कब्जा करने से दिनभर मेट्रो में चलने वाले यात्रियों को आने-जाने में काफी असुविधा होती है। शाम के समय ज्यादा भीड़ होने से स्थिति और भी भयानक रहती है, जिससे असामाजिक तत्वों का खतरा भी बना होता है। अतिक्रमण होने से अक्सर इन सड़कों और चौराहों पर जाम लग जाता है, जिस कारण वातावरण में प्रदूषण की समस्या बढ़ती ही है, ईंधन की बर्बादी होती है। आखिर कब दिल्ली प्रशासन की आंखें अतिक्रमणमुक्त कराने के लिए खुलेंगी।

प्रवीण कालड़ा, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर

पंजाब केसरी DELHI
18 दिसम्बर, 2022 ▶ रविवार

मास्टर प्लान 2041 में मिले नाइट इकोनॉमी को बढ़ावा: एलजी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): राजधानी के कायाकल्प को लेकर रोजाना जनहित में महत्वपूर्ण फैसले ले रहे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अब दिल्ली मास्टर प्लान 2041 (एमपीडी-2041) में नाइट इकोनॉमी को बढ़ावा दिये जाने और झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास पर जोर देने की बात कही है। इस उददेश्य के चलते उन्होंने एमपीडी-2041 ड्राफ्ट की समीक्षा के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अधिकारियों के साथ बैठक की। ड्राफ्ट के कुछ अध्यायों की जांच कर उसमें जरूरी बदलाव के सुझाव दिए गए है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नया मास्टर प्लान शहर के नियोजित विकास, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला और दिल्लीवासियों की सुविधा के अनुकूल होना चाहिए। मास्टर प्लान अगले 20 सालों को ध्यान में रखकर दिल्ली के विकास का खाका होता है। दो खंडों वाले इस नए ड्राफ्ट मास्टर प्लान में 22 अध्याय हैं जिसमें नाइट लाइट, वायु प्रदूषण, दिल्ली के विकास आदि को लेकर कई बातें शामिल की गई हैं। एलजी का मानना है कि बीते कुछ दशकों में जिन नीतियों को लागू किया, उनसे दिल्ली में गंदगी बढ़ने के साथ झुग्गी-बस्तियों के साथ ही अनधिकृत कॉलोनियों व झुग्गियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। इसीलिए इस बार ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिनसे शहर को साफ-सुथरा करने में मदद मिले। साथ ही झुग्गी में रहने वालों के जीवन स्तर में भी सुधार हो सके।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक भास्कर
PER नई दिल्ली | सोमवार, 19 दिसंबर, 2022

एलजी ने द्वारका में एयरपोर्ट के नाले और 5 जल निकायों के निर्माण का निरीक्षण किया

परियोजना के बाद एयरपोर्ट और द्वारका क्षेत्र के आसपास नहीं होगा जलभराव

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना रविवार को द्वारका में हवाई अड्डे का नाला और 5 जल निकायों के निर्माण का निरीक्षण किया। इन परियोजनाओं को पूरा होने के बाद आईजीआई एयरपोर्ट और द्वारका क्षेत्र के आसपास जलभराव नहीं होगी। डीडीए का यह महत्वाकांक्षी योजना मई 2023 तक पूरा किया जाएगा। दिल्ली सरकार के वृक्षारोपण की अनुमति लंबित होने के कारण पिछले 2 वर्षों से परियोजना अटकी हुई थी।

अधिकारियों ने बताया कि डीडीए के द्वारा द्वारका में 5 वाटर टैंक बनाया जा रहा है। जिनका उपयोग मानसून के दौरान अतिप्रभावित वर्षा जल के भंडारण के लिए किया जाएगा। एक बार पूरा हो जाने के बाद इन जल निकायों में पानी की कुल भंडारण क्षमता 1.22 लाख घन मीटर होगी जो बारिश के पानी को सड़कों पर बहने से रोकेगी। दिल्ली सरकार से। अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल के दखल के बाद ही ट्री ट्रांस लोकेशन की अनुमति दी गई और 20 नवंबर को एयरपोर्ट ड्रेन का काम शुरू हुआ। हवाईअड्डे से बारिश के पानी की मात्रा, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर भारी बारिश के दौरान आईजीआई हवाईअड्डे के अंदर और आसपास गंभीर जलभराव हो जाता है। इस तरह यात्रियों को कई दिनों तक उड़ानें बाधित और रद्द करनी पड़ती हैं। भारी जलभराव ने कई मौकों पर एयरपोर्ट को बंद करने के लिए मजबूर किया। इससे आसपास के द्वारका सेक्टर 8 में भी बाढ़ आ गई, जिसमें कई प्रमुख सरकारी संगठन हैं। इस परियोजना अगले वर्ष जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए मानसून के महीनों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले प्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों की परेशानी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करेगी।

इस माह में 8 बार ड्रेन का दौरा कर चुके है एलजी

पिछले एक महीने में एयरपोर्ट ड्रेन का तीन बार दौरा कर चुके एलजी ने निर्माण का निरीक्षण किया उन्होंने रविवार को द्वारका सेक्टर-8 में स्थल निरीक्षण किया और जल निकासी का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए जनशक्ति और अन्य संसाधन बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों से खुदाई और ड्रेजिंग का काम अगले महीने तक पूरा करने का निर्देश दिया है।

अमर उजाला सोमवार, 19 दिसंबर 2022

एयरपोर्ट ड्रेन व जलाशयों का काम मई तक पूरा होगा

निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे उपराज्यपाल वीके सक्सेना। अमर उजाला

अमर उजाला ब्यूरो

आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास जलभराव की नहीं होगी समस्या

05 जल निकायों में 1.22 लाख घन मीटर पानी का होगा भंडारण

जलभराव के कारण नहीं आएगी दिक्कत

मौजूदा दो नालियों में आईजीआई एयरपोर्ट से भारी मात्रा में बारिश के पानी की निकासी के लिए उचित इंतजाम नहीं होने से हर साल मुश्किल पेश आ रही थी। इससे आसपास के क्षेत्रों में गंभीर जलभराव की समस्या से लोग परेशान थे। भारी जलभराव के कारण कई बार एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। द्वारका सेक्टर-8 में भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई।

नई दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट से द्वारका आने जाने वाले यात्रियों को अगले मानसून में जलभराव से राहत मिलेगी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की देखरेख में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में बारिश के पानी को नजफगढ़ ड्रेन तक पहुंचाने के लिए जल निकासी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है। मई तक इन्हें पूरा कर लिया जाएगा। डीडीए की ओर से द्वारका क्षेत्र में पांच जल निकाय भी तैयार किए जा रहे हैं। इनका उपयोग वर्षा जल के भंडारण के लिए किया जाएगा। इनमें 1.22 लाख घन मीटर पानी का भंडारण किया जाएगा। इससे द्वारका, आईजीआई के आसपास के क्षेत्रों समेत गुरुग्राम से आवागमन करने वाले लाखों लोगों को राहत मिलेगी।

सूत्रों के मुताबिक, पिछले दो वर्षों से दिल्ली सरकार से पेड़ काटने या स्थानांतरण की अनुमति नहीं मिलने की वजह से परियोजनाएं रुकी हुई थीं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के दखल के बाद ही अनुमति दी गई। इसके बाद 20 नवंबर से एयरपोर्ट ड्रेन के लिए कार्य शुरू किया गया। एक महीने में एयरपोर्ट ड्रेन का उपराज्यपाल तीन बार दौरा कर चुके हैं। रविवार को भी उन्होंने द्वारका सेक्टर-8 में निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल निकासी के कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। इसके लिए संसाधनों को बढ़ाने का भी उन्होंने निर्देश दिया। सक्सेना ने इस मौके पर जलाशयों के लिए तयशुदा स्थानों का निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों से अगले महीने तक खुदाई और ड्रेनिंग का काम पूरा करने को कहा।

2.5 किलोमीटर लंबी एयरपोर्ट ड्रेन के लिए 72,000 घन मीटर मिट्टी हटाने की जरूरत होगी। अब तक 8200 घन मीटर मिट्टी निकाली जा चुकी है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NAME OF NEV MONDAY, 19 DECEMBER, 2022 | NEW DELHI ---DATED----------

THESE PROJECTS WILL ELIMINATE WATERLOGGING IN AND AROUND IGIA & DWARKA

L-G Saxena inspects construction of Airport dra water bodies in Dwarka; to be completed by Ma

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: Delhi Lieutenant Governor V K Saxena on Sunday inspected the construction of the Airport drain and five water bodies in Dwarka.

Travellers bound to the IGI Airport and the residents of the Dwarka Sub-city in the national Capital are set for a big relief from flooding and waterlogging during the monsoons, starting next year. A major drainage project to channelise the rain and storm water discharge from the IGI Airport to Najafgarh Drain, being executed by Delhi Development Authority (DDA) under the guidance of Lieutenant Governor V K Saxena, is fast progressing and will be completed by May 2023.

DDA, at the same time, is also creating 5 water bodies in the Dwarka region that will be used for storing the overflowing rain water during the monsoons. Once completed these water bodies will have the total storage capacity of 1.22 lakh CuM of water that will prevent the rain water from flooding onto the streets.

This major project was stuck for the last two years due to pending permissions for tree cutting/translocation from the Delhi government. It was only after the L-G's intervention that permission for tree translocation was given and the work on the airport drain commenced on November 20.

The L-G, who has already undertaken three visits to the Airport Drain in the last one month, inspected the construc-

tion site at Dwarka Sector – 8 on Sunday and directed the officials to enhance the manpower and other resources to complete the drainage work at the earliest. Saxena also inspected the sites for these water bodies and asked the officials to complete the digging and dredging work by next month.

The 2.5 km long airport drain will require 72,000 CuM of earth removal out of which 8,200 CuM of earth has been removed so far. The lining work has also begun simultaneous so as to maintain the pace of the work and cause minimum disruption of traffic. The L-G has issued strict instructions to finish the construction work by May 20 next year and warned against any laxity on part of the officials.

It is pertinent to mention that the existing 02 drains at the IGI Airport have proven insufficient for discharging the huge amount of rain water from the airport which has often resulted in severe waterlogging in and around the IGI Airport during heavy rains and thus causing disruption and cancellation of flights for several days major inconvenience to the passengers. Heavy waterlogging even forced closure of the IGI Airport on several occasions. This also caused flooding in the adjoining Dwarka Sector 8, which houses several prominent Government organizations. During the L-G's visits to Dwarka, the residents had also complained of crippling waterlogging in several areas.

Saxena said construction of the airport drain along with the creation of water bodies will be a big relief for the air travellers and the local residents of Dwarka. He said during the monsoon, the overflowing water from the airport as well as from the streets of Dwarka could be channelized to these water bodies. This project will also ensure hassle-free movement of delegates and dignitaries visiting the national Capital during the monso
Summ
The
capabl
of wate
peak r
start fr
premis
way tra
bound
and w
Trunk
would
rain wa
While t
within
be done
DIAL;
constru
railway
constru
ried ou
drain w
will ha

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

— THE HINDU —
NAME OF NEWSPAPERS
MONDAY
December 19, 2022
---DATED---

Investors in limbo as DDA's land pooling policy, first notified in 2013, yet to take off

Muneef Khan
NEW DELHI

A view of a DDA land in Delhi.
FILE PHOTO

Investors see little hope of realising their dreams anytime soon with no signs of proposed amendments to the Delhi Development Act 1957 – to make land pooling mandatory – in the ongoing Parliament session

About eight years ago, retired bank employee Raj Kataria joined a housing society that bought over six acres of land in north-west Delhi's Ladpur village. Mr. Kataria hoped to build a home after the Delhi Development Authority identified the village under its Land Pooling Policy (LPP).

However, with the LPP yet to be implemented on ground – it was first notified in 2013 and then in 2018 – Mr. Kataria and fellow investors have been left waiting inordinately. They see little hope of realising their dreams anytime soon with no signs of proposed amendments to the Delhi Development Act 1957 – to make land pooling mandatory – in the ongoing Parliament session.

"We visit the land over five times a year to ensure it has not been encroached upon. The land's value has fallen since the policy never took off and selling it would be a loss. Fellow investors frequently call to check the policy's status. Most of them have spent their life's savings on it," Mr. Kataria said.

104 villages

The LPP identified 104 villages for land pooling and aimed to provide 17 lakh dwelling units for roughly 80 lakh people. These villages have been divided into six zones and sub-divided into 129 sectors. While the DDA acts as a facilitator, the urban body has struggled to garner interest among landowners and failed to achieve the primary eligibility criteria of minimum 70% participation of owners along with 70% of the land being contiguous.

In the run-up to the recent MCD polls, Union Minister Hardeep Puri said the proposed amendments to help remove these roadblocks "will come in the next Parliament session", after he first announced the plan in early March.

However, a senior official at the Ministry of Housing and Urban Affairs said the Union Cabinet has yet to approve the amendments. The Cabinet approval "will take time", the official said, adding that the Bill to amend the Act has not been introduced.

One of the proposed amendments is to make pooling of land mandatory for the remaining landowners if 70% owners have already agreed. The other amendment would grant power to the Centre to declare land pooling mandatory, even if the minimum criteria of 70% participation and 70% contiguity are not achieved.

For the likes of Sunil Pahwa, part of a housing society that bought five acres of land in 2015, in Samaspur village, the delay has pushed investors to a conclusion that the "authorities have no will" to execute the LPP.

"Nine years is a long time. We would have built our houses by now. People in the housing societies who encouraged fellow members to invest are now getting phone calls from landowners who want their money back. When a policy like this isn't implemented, people like us bear the brunt, not those who drafted it," said Mr. Pahwa.

Like Mr. Pahwa, H.K. Yadav, a farmer, has been eagerly waiting for the LPP to kick-off, as he hopes it will help develop his village near Najafgarh.

He and Mr. Pahwa highlighted that apart from the amendments, the parallel strategy of the DDA issuing conditional notices to form landowner consortiums has not worked out, especially in three sectors – Sector 10A (Zone N) and Sectors 2 and 3 (Zone P-II).

The notices were issued in mid-May on the condition that landowners, who expressed interest in the LPP, negotiate and convince the remaining landowners to pool their land within 90 days. However, according to a senior DDA official privy to the matter, the process is still going on despite the 90-day period having passed.

"The LPP is a people's policy and its execution depends on their participation. Those who expressed interest in the policy and purchased land were aware of this. Consultations are going on in the six sectors where conditional notices were issued," said the official.

Since the window for land pooling applications was first opened in 2019, close to 7,100 applications have been received from landowners and around 7,400 hectares, of the 19,074 hectares of land, have been pooled till date. The deadline to express interest, which has been extended on numerous occasions, is December 31.